

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग-68

5838 राज-6/95/16

जयपुर, दिनांक :- 14-10-05

जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषय :- अनुसूचित जातियों को भूमि का पाँवर आफ अटानों के द्वारा अंधे ब्रैचान के संबंध में।

माननीया मुख्य मंत्री महोदया को संभागीय स्तर की बैठकों के दौरान यह जानकारी दी गई कि कतिपय क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को भूमि का ब्रैचान फर्जों § Fraudulent § तरीके से पाँवर आफ अटानों के माध्यम से किया जा रहा है।

उपरोक्त के संबंध में राजस्थान शासककारी अधिनियम 1955 की धारा 428 ब्रैचों में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/सहस्रिया जाति का व्यक्ति अपनी भूमि का अन्तरण, विक्रय, दान, वसोयत आदि किसी प्रकार से इनके भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता है तथा इन जातियों के व्यक्तियों द्वारा अगर पाँवर आफ अटानों को पाँवर अन्य किसी व्यक्ति को दी जाती है तो पाँवर आफ अटानों होल्डर ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिसको कि पाँवर आफ अटानों देने वाला स्वयं नहीं कर सकता अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहस्रिया जाति के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को पाँवर आफ अटानों दी जाती है तो पाँवर आफ अटानों होल्डर ऐसा कोई अन्तरण विक्रय, दान, वसोयत आदि उक्त भूमि का ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता जो, पाँवर आफ अटानों देने वाले व्यक्ति कि जाति में भिन्न हो अर्थात् अनुसूचित जाति के व्यक्ति का पाँवर आफ अटानों होल्डर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हो तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का पाँवर आफ अटानों होल्डर केवल अनुसूचित जनजाति के पक्ष में इसी प्रकार सहस्रिया जाति के व्यक्ति या पाँवर आफ अटानों होल्डर केवल सहस्रिया जाति के व्यक्ति के पक्ष में ही अन्तरण, विक्रय, वसोयत, दान आदि कर सकता है अगर उपरोक्तानुसार अन्तरण, विक्रय, वसोयत, दान नहीं किया जाता है तो ऐसा अन्तरण, विक्रय, दान आदि प्रारम्भ से ही शून्य होगा। ऐसी स्थिति में पंजीयन कार्यालयों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार के अन्तरण पंजीयन नहीं किए जायें।

अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि राजस्थान शासककारी अधिनियम, 1955 की धारा 428 ब्रैचों के अन्तर्गत इस प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति को भूमियों का ब्रैचान अन्य व्यक्तियों को पाँवर आफ अटानों के माध्यम से नहीं हो पाये। यदि विक्रयविलेख का पंजीयन प्रावधानों के उल्लंघन में पंजीयक/उप पंजीयकों द्वारा किया गया हो तो उसको जाँच कराकर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये व जमाबन्दों में अंकन नहीं किया जाये।

प्र-तिलिपि :- महा नि. होल्डर, पंजीयन, अजमेर को भेजकर देना है कि नि. अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सभी उक्त महा नि. होल्डर, पंजीयन, एवं सभी उप पंजीयक को आकर यह कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित करावे।

2. सचिव, वित्त विभाग को सूचनाार्थ प्रेषित है।

उप शासन सचिव 10/10/05

उप शासन सचिव 10/10/05